# नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1999


बहस

## एक समान कर ढांचा

**हमारा मत** है कि सभी राज्यों के लिए एक समान करनीति पर सहमति बनाकर केंद्र ने सही दिशा में कदम उठाया है।

आर्थिक सुधारों के इस दौर में कर सुधारों की गति काफी धीमी है। लेकिन इस दिशा में एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ है और लगभग सभी राज्य केन्द्र सरकार के इस प्रयास में शामिल हो गए हैं। मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वैट) को अपनाने के लिए सभी राज्य सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गए हैं। बिक्री कर के लिए भी न्यूनतम फ्लोर रेट तय करने की बात सामने आई है। यह एक अच्छी शुरुआत है और इससे देश में समान कर ढांचा लागू करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों और विदेशी निवेशकों की यह हमेशा से शिकायत रही है कि भारत में एक समान कर व्यवस्था न होने के कारण उन्हें काफी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जिस वस्तु पर एक राज्य में कोई कर नहीं है, उसी पर दूसरे में भारी कर है। नतीजतन बिना कर चुकाए एक राज्य से दूसरे में उस वस्तु की 'तस्करी' होती है। इसी तरह करों की दरों में विसंगति होने की वजह से व्यापारियों और उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।यह सही है कि राज्यों को कर लेने की छूट है, लेकिन इसका यह मतलब भी तो नहीं कि अन्य राज्यों और केन्द्र से विचार-विमर्श भी नहीं किया जाए। हमारा मानना है कि देश में एक समान कर व्यवस्था करने का यह कदम उचित और आवश्यक है।

प्रतिसम्पादकीय/इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस के निदेशक **जे.डी. अग्रवाल** का मत है कि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि एक समान करनीति लागू होने से देश को कई फायदे होंगे। उद्योगों को यह फायदा होगा कि एक जैसी कर की दरें होने से उनके लिए सामान और सेवाओं का अंतरराज्यीय बहाव पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा और उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि बिक्री कर घटने से उन्हें चीजें पहले से कम दाम पर मिलेंगी। इस तरह की कर व्यवस्था अमेरिका में लागू है और वहीं से प्रेरणा लेकर इसे भारत में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा नई व्यवस्था डब्ल्यू टी ओ की शर्तों के भी ज्यादा अनुकूल है, लेकिन इस अच्छे काम के कुछ बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। एक तो यह कि सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि वह नई व्यवस्था के कारण होने वाले राज्यों के कर घाटों को पाटने के लिए अपने खजाने से रकम देगी। इसका मतलब है कि सरकार को हजारों करोड़ के अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के लिए तैयार रहना होगा। क्या हमारी खस्ताहाल सरकार इस नए बोझ को झेलने की स्थिति में है? दूसरे, भारत सरकार कर की दरों में रियायत या टैक्स हॉलीडे जैसे प्रलोभन दे कर उद्योगपतियों को देश के अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करती रही है। अब एक समान दरें लागू होने से उस नीति का क्या होगा?